n style='mso-tab-count:1'>

Title: Need to extend loan-waiver scheme to the small and marginal farmers who have availed housing loans from Rajasthan State Cooperative Housing Society-Laid.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2008-09 में ग्रामीण किसानों के 50,000 रूपये तक के ऋणों को माफ किया गया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सहकारी आवास ऋणों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस कारण राजस्थान राज्य सहकारी आवासन कर्मचारी परेशानी में है जिनका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण किसानों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सस्ते ब्याज पर आवास ऋण उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के आवासन ऋण उपलब्ध करवा कर सहकारी आवासन संघ ने राज्य के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मेरी मांग है कि इन गरीब ग्रामीण, लघु एवं सीमान्त कृषकों के सहकारी आवास ऋणों को भी कर्ज माफी संबंधी बजटीय घोषणा 2008-09 में सम्मिलित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमान्त एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को वास्तविक रूप से 50 हजार रूपये के कर्ज माफी का लाभ मिल सके।